अब राजस्थान के 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने सोमवार रात पोस्ट कर के इस उपलब्धि की औपचारिक घोषणा की

जयपुर, 31 मार्च। प्रदेश के 22 जिलों के बाद, अब दौसा एवं करौली जिले में भी कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ होने लगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार रात अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट करके यह बड़ी घोषणा की।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का महत्वाकांक्षी संकल्प लिया है। इस क्रम में वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट में यह कार्य चरणबद्ध रूप से वर्ष 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल प्रदेश के 22 जिलों में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के दो ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अब जयपुर विद्युत वितरण निगम के दौसा एवं करौली जिले भी इससे जुड़ने जा रहे हैं।

फिलहाल जयपुर डिस्कॉम के 7 जिलों,धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग एवं भरतपुर, के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध हो रही है।

इसी तरह अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों-अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुन्झुनू, सीकर, चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर तथा जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों, जालौर, सिरोही

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

एवं पाली में भी कृषकों को दिन के दो ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति की जा रही है।

विगत समय में जयपुर डिस्कॉम ने दौसा एवं करौली जिलों में विद्युत तंत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। दौसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही, दौसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एमवीए की क्षमता वृद्धि की गई है। वहीं, करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एमवीए की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसका लाभ दौसा जिले में 52,460 तथा करौली जिले में 35,341 कृषि

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली देने का महत्वाकांक्षी संकल्प अपनी सरकार के पहले बजट में लिया था तथा वर्ष 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करने का समय निर्धारित किया था।**
- **सरकार का मानना है कि दिन में बिजली की आपूर्ति किसान को कड़ाके की सर्दी व बारिश में रात को सिंचाई कार्य करने की मजबूरी नहीं रहेगी तथा जंगली जानवरों का खतरा भी नहीं रहेगा।**

उपभोक्ताओं को दिन में बिजली आपूर्ति के रूप में मिलेगा तथा कड़ाके की सर्दी एवं बारिश में रात्रि के समय सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी।

आज से टोल पर नकद भुगतान बंद केवल डिजिटल पेमेंट होगा

नई दिल्ली, 31 मार्च। देशभर में सड़क इस्तेमाल करने वाले लोग एक अप्रैल से टोल चार्ज नकद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम अपनाने जा रहा है। हाईवे यात्रा को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़े कदम के तौर पर एनएचएआई देशभर के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पर पूरी तरह से रोक लगा देगा।

एक अप्रैल से यात्रियों को टोल चार्ज सिर्फ फास्टैग या यूपीआई जैसे

- **हाईवे यात्रा की आधुनिक बनाने के लिए एनएचएआई ने यह नया पारदर्शी कदम उठाया**

डिजिटल तरीकों से ही देना होगा। इस कदम का मकसद नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन को अधिक कुशल बनाना और ज्यादा पारदर्शिता लाना है।

अधिकारियों का मानना है कि पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम से गाड़ियां टोल प्लाजा से अधिक तेजी से निकल पाएंगी, जिससे लंबी लाइनें नहीं लगेंगी और यात्रा का समय बचेगा। टोल बूथ पर तेजी से प्रोसेसिंग होने से ईंधन की खपत कम होने और प्रदूषण में भी कमी आने की संभावना है।

इस बदलाव से कुछ यात्रियों को परेशानी हो सकती है, खासकर उन लोगों को जो डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार नहीं हैं।

जयपुर में गैस की कालाबाजारी पर एक्शन, 118 सिलैंडर व उपकरण जब्त

जिला रसद अधिकारी के तीन विशेष दलों ने शहर में सघन निरीक्षण व कार्यवाही की

जयपुर, 31 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार तथा राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों की अनुपालना में, जयपुर शहर में घरेलू एवं व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता एवं निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अवैध रिफिलिंग, भण्डारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी प्रियव्रत सिंह चारण द्वारा 03 विशेष प्रवर्तन दलों का गठन कर शहर में सघन निरीक्षण एवं कार्रवाही की गई। इन दलों में प्रवर्तन अधिकारियों एवं निरीक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया गया।

कार्रवाहियों के दौरान, कुल 118 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटे, 2 उपकरण , 3 रिफिलिंग मोटर, 1 रेगुलेटर एवं 1 पिकअप वाहन जब्त किए गए हैं। अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई हो रही हैं।

- **खो नागोरियान में नारायण सिटी, जेएनयू अस्पताल के पास, आगरा रोड, गौरव जनरल भंडार व बिंदायका में घरेलू व व्यवसायिक गैस सिलैंडर, रिफिलिंग मोटर आदि उपकरण पकड़े गये।**

उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा जयपुर शहर में कार्यवाही हेतु तीन विशेष प्रवर्तन दलों का गठन किया गया। दल "ए" में कविता शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व सुनिता चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक विशेष प्रवर्तन दल "बी" में पूजा शर्मा प्रवर्तन अधिकारी व विजयलक्ष्मी शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक एवं विशेष प्रवर्तन दल "सी" में निर्मला चौधरी प्रवर्तन अधिकारी व प्रिया गंगवानी प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच की गई।

पुलिस थाना खो-नागोरियान क्षेत्र में नारायण सिटी, जेएनयू हॉस्पिटल के पास संयुक्त कार्रवाई के दौरान, अवैध रिफिलिंग की पुष्टि होने पर 74 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर, 1 इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 रिफिलिंग मोटर तथा 1 पिकअप वाहन जब्त किया गया। इसी प्रकार, आगरा रोड स्थित गौरव बर्तन भंडार एवं जग्गा की ढाणी में दबिश के दौरान 22 गैस सिलेंडर एवं एक उपकरण जब्त किए गए। भांकरोटा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 8 गैस सिलेंडर, 1 कांटा एवं एक उपकरण जब्त किया गया, वहीं बिन्दायका क्षेत्र में की गई कार्रवाई में 14 गैस सिलेंडर, 1 कांटा तथा 1 रेगुलेटर रबर पाइप सहित जब्त किया गया।

उल्लेखनीय है कि जयपुर शहर में अवैध गैस रिफिलिंग एवं कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा संचालित 'ऑपरेशन प्रवर्तन - सतर्क नागरिक, सुरक्षित शहर' अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गैस रिफिलिंग, भण्डारण अथवा कालाबाजारी से संबंधित सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि समय रहते कठोर कार्रवाई कर आमजन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके।

ईरान 1 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के समय के अनुसार यह रात 10:30 बजे का समय होगा। ईरान ने कहा है कि हर हमले के बदले इन कंपनियों की यूनिट्स को तबाह किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को तुरंत अपने कार्यस्थलों से हटने की चेतावनी भी दी गई है। ईरान ने 15 बड़ी अमेरिकी कंपनियों की सूची जारी की है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एपल, इंटेल, आईबीएम, टेस्ला और बोइंग जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा डेल, एचपी, सिस्को, ओरेकल और जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के नाम भी सामने आए हैं। इससे साफ है कि ईरान अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहना चाहता।

बार-बार पश्चिम एशिया में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है, अब "नाटो की पुनर्समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि कुछ सदस्य देशों ने स्पष्ट रूप से अपने एयरबेस का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।"

इस बीच, ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के एक कॉन्फ्रैंस स्थल के पास स्थित एक लक्ष्य पर बमबारी की, जहाँ लगभग 200 वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी पश्चिम एशिया में अपने अभियानों पर चर्चा कर रहे थे। बड़ी संख्या में अधिकारियों के हताहत होने की आशंका है, हालांकि अमेरिकी सेना की ओर से अभी तक इस हमले की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

ईरान ने दिन के दौरान, कुवैत के एक बड़े तेल टैंकर को भी निशाना बनाया, जिससे आग लग गई और वैश्विक बाजार के लिए तेल परिवहन बाधित हो गया। इन दोनों हमलों को एक बार फिर अत्यंत सटीक माना जा रहा है, जिससे बाहरी स्रोतों से खुफिया जानकारी मिलने की आशंका भी जताई जा रही है।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य (स्ट्रेट) के लगातार बंद रहने और तेल एवं ऊर्जा सुविधाओं पर बढ़ते हमलों ने तेल की वैश्विक कीमतों को और बढ़ा दिया है। नवीनतम तेल बाजार रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत लगभग 110 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है।

अमेरिका में गैस की कीमतें बढ़कर 4 डॉलर प्रति गैलन तक पहुँच गई हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए बड़ा झटका हैं और ट्रंप प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ा रही हैं।

अमेरिकन रक्षा मुख्यालय पेंटागन में हुई एक ब्रीफिंग के दौरान, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका को पूरी जानकारी है कि रूस और चीन कहाँ, क्या कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका इन चुनौतियों का सीधे सामना कर रहा है और अपनी रणनीति के अनुसार उनसे निपट रहा है।

उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका रूस और चीन की गतिविधियों पर करीबी नज़र रखे हुए है। ट्रंप ने ईरान के मुद्दे से निपटने में फ्रांस की गैर-सहयोगी भूमिका की भी आलोचना की।

अब अमेरिकी सैन्य नेतृत्व यह स्वीकार करने लगा है कि ईरान को कहीं और से सूचना मिल रही है, जिससे उसके हमले अधिक सटीक और प्रभावी हो रहे हैं। अमेरिका ईरान से बातचीत करने और समझौता करने की अपील कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

सूरत के एक मकान में विस्फोट, पांच की मौत

सूरत, 31 मार्च। गुजरात के सूरत के लिंबायत क्षेत्र में मीठी खाड़ी के पास स्थित एक मकान में केमिकल में विस्फोट होने से भीषण आग लगने से 5

- **मकान में साड़ियों का काम होता था व ज्वलनशील केमिकल रखा था, जिसमें ब्लास्ट से आग लगी।**

लोगों की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। बताया गया एक घर में साड़ियों का काम होता था, जिसके चलते वहां ज्वलनशील केमिकल रखा गया था।

वकीलों को हटाना जेडीए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नवंबर 2025 को जेडीए ने प्रताप सिंह को बिना कारण बताए हटा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत में 11 नवंबर 2025 को जोनल कमिश्नर द्वारा जारी रिपोर्ट पेश की, जिसमें याचिकाकर्ता समेत कुछ अन्य वकीलों के कार्य को संतुष्टिपूर्ण बताया था।

अदालत ने दूसरी याचिका, जिसे अपने फैसले में उद्धृत किया, वह राम सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्हें वर्ष 2021 में, यानी पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में जेडीए से हटाया गया था। रामसिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता साहिल शर्मा पैरवी के लिए उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता राम सिंह के पास वर्ष 2012 में जेडीए द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र हैं, जिसमें उनके कार्य को संतुष्टिपूर्ण बताया गया था। आर.एन.माथुर ने अदालत को बताया कि, उनके मुवक्किल राम सिंह को भी जेडीए प्रशासन ने हटाने का कोई कारण नहीं बताया, परंतु उन्हें तत्कालीन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आदेश पर हटाया गया था। राम सिंह को हटाने के तरीके से स्पष्ट होता है कि यह फैसला उन वकीलों को खुश करने के लिए था, जो तत्कालीन सरकार के करीबी थे और मंत्री की जान-पहचान के थे।

जेडीए की ओर से इस मामले में कहा गया कि सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई थी, यह जेडीए के कार्मिक नहीं थे। ऐसे में इन अधिवक्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है कि वे अपनी सेवाएं जारी रखने का अधिकार प्राप्त कर सकें। इस पर अदालत ने कहा कि अधिवक्ता न्यायिक प्रणाली में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, एक वकील को नौकर की भांति नहीं समझा जा सकता, उन्हें पद से हटाने अथवा लगाने के लिए एक ठोस वजह व कारण होना चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जेडीए ने इन अधिवक्ताओं को हटाते समय ऐसा कोई कारण या वजह नहीं बताई, जिससे उनकी कार्यशैली पर असंतोष जाहिर हो। इस मामले में अब यह देखना है कि अधिवक्ताओं को हटाने का कोई कारण था या जेडीए अधिकारियों ने अपनी मनमानी की थी। अदालत ने आगे कहा कि जेडीए की खुद की गाइडलाइन कहती कि अगर जोनल कमिश्नर अधिवक्ता से असंतुष्ट है तो उसे हटा सकता है, परंतु जेडीए की ओर से इस संबंध में कोई दस्तावेज अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में 25 ईनामी नक्सलियों ने समर्पण किया

बीजापुर, 31 मार्च। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलवाद के खात्मे की तय समय सीमा के अंतिम दिन, आज मंगलवार को बस्तर आईजी सुन्दरराज

- **इनके पास से 93 घातक हथियार, 7.2 किलो सोना, व 2.90 करोड़ रु. नकद बरामद हुए।**

पी., सीआरपीएफ के डीआईजी बी.एस. नेगी, बीजापुर के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव सहित, कई वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष 25 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 1.47 करोड़ का इनाम घोषित था। इन नक्सलियों ने एलएमजी, एके-47, एसएलआर, इंसास सहित, कुल 93 घातक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है। पहली बार नक्सलियों के पास से 2.90 करोड़ रुपये नकद और लगभग 7.2 किलोग्राम सोना बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत करीब 11.16 करोड़ रुपये आंकी गई है। इनके पास मिले हथियारों में 4 एके-47 और 9 एसएलआर राइफलें जैसे आधुनिक हथियार भी शामिल हैं।

ईरान के इस्फहान शहर पर अमेरिका ने भारी हमला किया

तेहरान/कुवैत सिटी/ बेरूत/ बगदाद, 31 मार्च। अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के ऐतिहासिक शहर इस्फहान पर जबरदस्त हमला किया है। इस शहर की आबादी लगभग 23 लाख है। यहां बदर मिलिट्री एयरबेस भी मौजूद है। जोरदार धमाकों और आग की लपटों से आज सुबह तक आसमान में दहशत रोशन रही। हिजबुल्लाह ने भी इज़रायली सेना पर हमलों का दावा किया है।

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शियों ने इस्फहान में हमले के कई वीडियो तैयार किए हैं। इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा और सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। यह ईरान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहां कपड़ा और इस्पात की मिलें हैं। यहां ईरान का

- **यह शहर एतिहासिक पृष्टभूमि तथा औद्योगिक इकाइयों के कारण विख्यात है**

महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र (नतंज) और सैन्य मिसाइल बनाने के कारखाने भी हैं। इसके कारण यह अकसर चर्चा में रहता है। इस बीच हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल की मिसगाव अम बस्ती में एक सैन्य चौकी को निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान के अल-क़ंतारा और तैबेह कस्बों के बीच सड़क पर मौजूद एक इजराइली मर्कवा टैंक पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हमले में टैंक जल गया।

बीजू का अपमान "उडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। राज्य के विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि पार्टी सांसद द्वारा व्यक्त विचार "पूरी तरह उनके व्यक्तिगत विचार" हैं और सरकार के रुख को नहीं दर्शाते। उन्होंने कहा, "ऐसी टिप्पणियाँ बहुत ही अनुचित हैं और किसी भी परिस्थिति में अपेक्षित नहीं हैं। इनसे न केवल मुख्यमंत्री मांझी, बल्कि हम सभी को गहरी पीड़ा हुई है।"

इस मामले में राज्य भाजपा की रक्षात्मक स्थिति समझ में आती है, क्योंकि लोगों के मन में बीजू पटनायक के प्रति गहरा सम्मान है। बीजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जो आमतौर पर संयमित भाषा के लिए जाने जाते हैं, ने असामान्य रूप से कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक स्वतंत्रता सेनानी और सम्मानित नेता के खिलाफ ऐसे "बेतुके और पूरी तरह झूठे" बयान देने वाले दुबे को मानसिक चिकित्सक से परामर्श लेने की जरुरत है।

भाजपा के भीतर भी प्रतिक्रियाएँ कम नहीं रहीं। पार्टी नेता और हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित दिलीप रे ने 'एक्स' पर लिखा: "बीजू बाबू का जीवन साहस, त्याग, दूरदृष्टि और अडिग देशभक्ति का प्रमाण था। वे केवल ओडिशा के एक महान नेता ही नहीं थे, बल्कि उन दुर्लभ राष्ट्रिनर्माताओं में से एक थे, जिनके जीवन और कार्य ने भारत के राजनीतिक और रणनीतिक इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनके इस असाधारण योगदान को हल्की और सनसनीखेज राजनीतिक टिप्पणियों तक ले आना न केवल अनुचित है, बल्कि अत्यधिक असम्मानजनक भी है।"

बीजद ने सोमवार को राज्यसभा में वॉकआउट किया। एक दिन पहले, पार्टी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार से सम्बंधित संसदीय स्थायी समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके अध्यक्ष दुबे हैं।

दुबे के ही पार्टी सहयोगी बैजयंत पांडा ने, बिना नाम लिए, कहा कि पटनायक की देशभक्ति पर सवाल उठाना "अकल्पनीय और पूरी तरह बेतुका एवं हास्यास्पद" है।

ओडिशा के जानकारों का कहना है कि दुबे की टिप्पणियाँ राज्य में "अंजैया क्षण" जैसी स्थिति पैदा कर सकती हैं। ज्ञातव्य है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री टी. एन. अंजैया का सार्वजनिक अपमान किया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में, एन. टी. रामाराव की तेलुगु देशम पार्टी ने तेलुगु गौरव के मुद्दे पर भारी जीत हासिल की थी।

'केरल में हर साल दो गैस सिलेंडर मुफ्त देगी भाजपा'

तिरुवनंतपुरम, 31 मार्च। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने केरल विधानसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र मंगलवार को जारी कर दिया। "यही बदलाव है, यही विकसित केरल है" थीम पर आधारित इस घोषणापत्र में राज्य के समग्र विकास का रोडमैप पेश किया गया है, जिसमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक कल्याण योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने तिरुवनंतपुरम स्थित श्री मूलम क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, टीवी-20 पार्टी के मुख्य समन्वयक साबू जैकब, बीडीजेएस के प्रदेश अध्यक्ष तुषार वेल्लापल्ली और तिरुवनंतपुरम के मेयर

- **भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया**

वीवी राजेश सहित, अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।

भाजपा ने घोषणापत्र में आम जनता, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी घोषणाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें गरीब परिवारों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, प्रत्येक घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पेयजल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करना प्रमुख हैं। इन योजनाओं के जरिए पार्टी ने सीधे तौर पर आम मतदाताओं को साधने की कोशिश की है।

'अमेरिका व्यर्थ ही ऐसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निशाना वॉशिंगटन को बनाया है। उनका यह दावा, कि संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे युद्ध का समर्थन कर रहा है, "जिसे वह जीत नहीं सकता", अमेरिकी विदेश नीति की रणनीतिक सुसंगतता पर उनके गहरे संदेह को दर्शाता है। वे ईराक से लेकर अफगानिस्तान तक, एक पैटर्न देखते हैं, अत्यधिक विस्तार (ओवररीच) का, जहाँ विशाल संसाधन खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थायी राजनीतिक परिणाम नहीं मिलते। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया में भी यही तर्क लागू हो रहा है: बिना विश्वसनीय अंतिम रणनीति के लगातार बढ़ता हुआ युद्ध।

उनकी टिप्पणियों का अधिक विवादास्पद, और राजनीतिक रूप से विस्फोटक हिस्सा उस कथित घटना से जुड़ा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच एक उच्चस्तरीय कूटनीतिक बातचीत में एलन मस्क की मौजूदगी का दावा किया गया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे आधिकारिक तौर पर खारिज किया है, पर सैक्स इस प्रकरण, चाहे वास्तविक हो या अनुमानित, का उपयोग अमेरिका में संवैधानिक व्यवस्था के पतन के बड़े मुद्दे को रेखांकित करने के लिए करते हैं।

यहाँ उनकी आलोचना विदेश नीति से हटकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ जाती है। सैक्स का तर्क है कि राज्य संचालन के मामलों में तकनीकी अरबपतियों का बढ़ता प्रभाव सार्वजनिक सत्ता और निजी शक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रहा है। जब अपार आर्थिक ताकत रखने वाले, निर्वाचित न हुए व्यक्ति औपचारिक या अनौपचारिक रूप से कूटनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल दिखाई देते हैं, तो यह जवाबदेही और लोकतांत्रिक वैधता के मूलभूत प्रश्न उठाता है। उनका कथन कि, "सरकार को खरीद लिया गया है" जानबूझकर बोला गया भड़काऊ कथन है, साथ ही यह एक व्यापक बहस को दर्शाता है कि केन्द्रित संपत्ति अब नीतिगत परिणामों को इस तरह प्रभावित कर रही है, जो संस्थागत नियंत्रण और संतुलन को दरकिनार कर देता है।

समग्र रूप से, सैक्स की टिप्पणियाँ एक ऐसी विश्वदृष्टि को दर्शाती हैं, जिसमें आज के संघर्ष अलग-थलग घटनाएँ नहीं, बल्कि गहरे संरचनात्मक संकटों के लक्षण हैं, शासन, वैश्विक व्यवस्था और आर्थिक असमानता के संकट। इस दृष्टिकोण में, पश्चिम एशिया का संघर्ष क्षेत्रीय या वैचारिक विवादों से अधिक तेजी से बदलती दुनिया को संभालने में बड़ी शक्तियों की विफलता को उजागर करता है।

भारत के पर्यवेक्षकों के लिए, सैक्स की टिप्पणियाँ दोहरे अर्थ रखती हैं। एक ओर, वे आपस में जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दूरस्थ संघर्षों में उलझने के जोखिम को रेखांकित करती हैं। दूसरी ओर, वे शक्ति के बदलते स्वरूप को उजागर करती हैं तो जहाँ राज्य, बाज़ार और तकनीकी अभिजात वर्ग तेजी से अप्रत्याशित तरीकों से एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं।

चाहे कोई उनके निष्कर्षों से सहमत हो या नहीं, लेकिन सैक्स एक असहज प्रश्न को सामने रख रहे हैं: ऐसी दुनिया में, जहाँ युद्धों के स्पष्ट विजेता नहीं होते और शासन स्वयं विवादित प्रतीत होता है कि आखिरकार सत्ता किसके हाथ में है?

नालंदा : शीतला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एसपी भारत सोनी के अनुसार, अत्यधिक गर्मी और भारी भीड़ इस हादसे की मुख्य वजह रही। उन्होंने बताया कि ठंडे पानी में स्नान के बाद जब महिलाएं मंदिर परिसर में प्रवेश कर रही थीं, तभी दम घुटने और पानी की कमी के कारण कई महिलाएं बेहोश होकर गिरने लगीं। इससे अफरा-तफरी मच गई और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते यह दुखद घटना घटी।

इस बीच केंद्र और राज्य सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन विभाग से 04-04 लाख रुपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से (सीएमडीआरएफ) 02-02 लाख रुपये (कुल 06 लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।

पूर्व टेनिस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुए इसे ऐतिहासिक पल बताया। उन्होंने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी भाजपा के मंच से देश की सेवा करेंगे। रिजिजू ने कहा कि देशभर में लिएंडर पेस का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने टेनिस स्टार के भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि लिएंडर पेस 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्त के प्रत्यक्ष वंशज हैं।

पाँच साल के अंतराल के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वर्ष 2024 और 2025 में ब्रिक्स और एससीओ शिखर सम्मेलनों के इतर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठकों के बाद संबंधों में सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी।

शंघाई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के आउन्सलेट जनरल प्रतीक माथुर ने मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल और पूर्वी चीन की प्रमुख कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों के बीच एक बिज़नेस राउंड टेबल बैठक की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य भारतीय व्यवसायों के साथ सहयोग के अवसर तलाशना था।

प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए माथुर ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और यहाँ विश्व की सबसे युवा आबादी में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान करती है।

अपने संबोधन में माथुर ने भारत में उभरते क्षेत्रों, जैसे नई और नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, तथा सूचना प्रौद्योगिकी, में बढ़ती संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वैश्विक कंपनियों के साथ सतत विकास हेतु सहयोग के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएचडीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा का उद्देश्य विशेष रूप से शंघाई, जो चीन का वाणिज्यिक केन्द्र है, और तेजी से विकसित हो रहे झेजियांग तथा जियांग्सू प्रांतों में भारतीय व्यवसाय और उद्योग जगत के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि औद्योगिक चर्चाओं के अलावा, इस यात्रा का ध्यान प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ावा देने और बिज़नेस-टू-बिज़नेस (बी2बी) बैठकों को प्रोत्साहित करने पर भी केन्द्रित है। इन पहलों का उद्देश्य भारत की घरेलू क्षमताओं और नवाचार को सुदृढ़ करना है, साथ ही 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाना भी है।

विज्ञप्ति के अनुसार, इस राउंड टेबल में चीनी पक्ष से भी उच्चस्तरीय भागीदारी देखने को मिली, जिसमें एचएसबीसी और वूशी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी प्रमुख कंपनियाँ और वित्तीय संस्थान शामिल थे। उनकी भागीदारी में उभरते उद्योगों और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने की काफी रुचि दिखाई दी।

चर्चाओं के वैश्विक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए यूरोपीय व्यापारिक समूहों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और प्रस्तावित "इंडिया-यूरोपयन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट" से उत्पन्न हो रहे अवसरों पर अपने विचार साझा किए।

प्रतिभागियों ने लचीली और टिकाऊ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया, जिसमें भारतीय व्यवसायों और निवेश की केन्द्रीय भूमिका हो सकती है।

प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से संबंधित एक पुस्तिका के अनुसार, इसका उद्देश्य प